







# विचार

# थाली में खाना न छोड़ें

इन दिनों शादियों का मौसम है। देखने में आता है कि जितना दिखावा उत्तर भारत और खास तौर से झक्खहृ समाज की शादियों में होता है, वह शायद और कहीं नहीं। इसाइयों, मुसलमानों और सिखों में शादियां बहुत सादगी से होती हैं। यह बात काबिले तारीफ है। एक तरफ दहेजमुक्त भारत के सपने देखे जाते हैं और दूसरी ओर शादियों में इतना दिखावा बढ़ गया है कि युवा नौकरी की शुरुआत में ही इतना बड़ा कर्ज उठा लेते हैं कि दशकों तक उसे चुकाते हैं। शादियों के बारे में जब से कार्पोरेट द्वारा अपने उत्पादों को लोकप्रिय करने की अवधारणा फैलाई गई है तब से माना जाने लगा है कि अगर दूल्हा-दुल्हन के पास अमुक ब्रांड के कपड़े नहीं, गहने नहीं, डेस्टीनेशन वैडिंग नहीं, प्री-वैडिंग शूट, पांच सितारा होटल या फार्म हाऊस नहीं तब तक शादियां जैसे हो ही नहीं सकतीं। यही सब करके सोचा जाता है कि शादी को लोग हमेशा याद रखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि शादी के प्रांगण से बाहर निकलते ही सब भुला दिया जाता है, हमेशा याद रखने की बात तो दूर है। यूं भी जिन दिनों शादियां बड़े पैमाने पर टूट रही हों, उन दिनों एक दावत को कौन याद रखता है। यही हाल खाने का है। आजकल शादियों में इतनी प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं कि कायदे से आप सभी का एक-एक चम्मच भी नहीं खा सकते। ऐसा भी होता है कि लोग प्लेटों में खूब खाना परोसते हैं और आधा खाया, आधा छोड़ देते हैं। इस तरह भारी मात्रा में खाना बर्बाद होता है जबकि अपने ही देश में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। कहा जाता है कि एक बार संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत खाना बर्बाद हो जाता है। अगर इसके पैसे का हिसाब लगाया जाए तो यह लगभग 88000 करोड़ रुपए बैठता है। यदि यह पैसा बचे तो और कितने काम आ सकता है। अच्छी बात यह है कि राजस्थान के शहर जोधपुर में 5 साल पहले एक मुहिम शुरू की गई कि थाली में खाना न छोड़ें। इसकी शुरुआत समदड़ी के कुंजुनाथ जैन मंदिर से हुई थी। वहां जयंती लाल पारेख ने इसकी शुरुआत की। बताते हैं कि इसकी प्रेरणा उन्हें महाराष्ट्र से मिली। पारेख ने ऐसी 1000 थालियां बनवाईं जिनमें मोटे अक्षरों में लिखा था कि थाली में जूठन न छोड़ें। पारेख का मानना था कि थालियों पर ऐसा लिखवाने से लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और वे सोच-समझकर खाना लेते हैं। जल्दी ही इस मुहिम ने जोर पकड़ लिया और इसकी शुरुआत जोधपुर जैसे शहर में हुई। इसकी पहल जैन, महेश्वरी और खांची समाज के लोगों ने की। इसे लोगों और शादियों में काम करने वाले कैटरर्स का भी समर्थन मिला। वहां थालियों में लेजर की मदद से मोटे अक्षरों में लिखवाया गया कि कृपया जूठा न छोड़ें।

# संसद शारीरिक ताकत दिखाने की जगह नहीं

और एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं लेकिन संसद मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अन्य सांसदों ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई। वी.आई.पी.एफ.आई.आर. का बढ़ता चलन लोकतंत्र की मेहरात के लिए खतरनाक है।

सहात के लिए खतरनाक है।  
आरोपी व्यक्ति की आपराधिक मानसिकता के अनुसार ही क्रिमिनल मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास की शिकायत भी दर्ज हुई थी। यह अच्छा हुआ कि दिल्ली पुलिस ने एफ.आई.आर. में वह धारा दर्ज नहीं की। कुछ दिनों पहले बेंगलुरु के ए.आई.इंजीनियर अतुल सुभाष ने आपराधिक मामले से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी। सांसदों की तर्ज पर निचले स्तर पर एफ.आई.आर. का प्रचलन बढ़ा तो देश में आपराधिक मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। आम मामलों में सी.सी.टी.वी. फुटेज मीडिया को जारी हो जाते हैं। संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। इसलिए संसद दक्षहसा से जुड़े सभी सी.सी.टी.वी. फुटेज जारी होने चाहिए। जिससे लोकतंत्र के मंदिर में माननीयों के अभद्र आचरण को टोकापा होने से रोका जा सके।

का दाबारा हान स रोका जा सका। शुरूआती दौर में अपराधियों के सहयोग से विधायक और सांसद चुनाव जीतते थे। 'पान सिंह तोमर' जैसी फिल्मों में बताया गया है कि कैसे अपराधी ही संसद में पहुंचने लगे। वर्ष 2006 में जद (यू) और आर.जे.डी. सांसदों के बीच और साल-2009 में सपा के अमर सिंह और भाजपा के आहलूवालिया के बीच हाथापाई हुई थी। फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून पर चर्चा के दौरान सांसदों ने सदन में मिर्च स्प्रे फैंका था। इन घटनाओं से साफ है कि शालीन बहस की



बजाय संसद हुड़दंग और आपराधिक घटनाओं का अखाड़ा बनती जा रही है। इक्ष्वहसा कर रहे सांसदों के माननीय होने पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं लेकिन राज्यों में विधायिकाओं का सालाना लेखा-जोखा बनाने में कुछ अच्छी बातें भी सामने आ रही हैं।

इंज ऑफ लिविंग और छोटे मुकदमों की









डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पूर्व प्रधानमंत्री भारत टल  
अटल बिहारी वाजपेयी जी  
की 100वीं जन्म जयंती के  
अवसर पर

## ₹ 44,600 करोड़ लागत की देश की पहली केन-बेतवा नदी जोड़े राष्ट्रीय परियोजना का रिलान्यास तथा

### ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण

### 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमिपूजन

### माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में स्टाम्प और सिक्का जारी

## प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

के कद-कमलों  
द्वारा

परियोजनाओं के लाभ

### केन-बेतवा नदी जोड़े राष्ट्रीय परियोजना

- मध्यप्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर के 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एवं उत्तरप्रदेश के 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा। परियोजना से कुल 65 लाख परिवारों को मिलेगी पेयजल की सुविधा।
- जल विद्युत परियोजनाओं से हरित ऊर्जा में 130 मेगावॉट का योगदान एवं औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।
- चंदेल कालीन लगभग 42 पुरातन तालाबों का होगा विकास एवं पुनर्निर्माण।
- दौधन बांध के निर्माण से बाढ़ का बेहतर प्रबंधन होगा संभव।

### ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना

- 518 मेगावॉट क्षमता की यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से एक है।
- परियोजना से कृषि एवं उद्योग हेतु उपयोगी भूमि की बचत होगी।
- जल संरक्षण एवं हरित ऊर्जा उत्पादन से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने में सहयोग मिलेगा।

### अटल ग्राम सुशासन भवन

- अटल ग्राम सुशासन भवनों का निर्माण ग्राम पंचायतों को स्थायी भवन की सुविधा प्रदान करेगा।
- ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक कार्य करने, बैठकों के आयोजन एवं रिकॉर्ड प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

## गरिमामयी उपस्थिति

मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

सी.आर. पाटिल

केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

D11136/24

25 दिसंबर, 2024 | पूर्वाह्न 11:00 बजे | खजुराहो, जिला छतरपुर

सीधा प्रसारण

<http://pmindiawebcast.nic.in>

DD News

@Cmmadhyapradesh  
@jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh  
@jansamparkMP

JansamparkMP

लाइव : बायोडायरेक्स